ड्रिप सिंचाई बढ़ाने के लिए 500 करोड़ के पैकेज की मांग

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 25 दिसंबर

कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने कपास किसानों के खेतों में ड्रिप सिंचाई संयंत्रों की स्थापना के लिए आगामी बजट में 500 करोड़ रुपये का पैकेज दिए जाने की मांग की है। सीएआई कपास की पूरी मूल्य श्रृंखला के हिस्सेदारों का प्रमुख संगठन है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने एक बयान में कहा कि संगठन की सालाना आम बैठक (एजीएम) में कहा गया है कि भारत में 67 प्रतिशत कपास का उत्पादन वर्षा पर निर्भर इलाकों में होता है। ऐसे में कपास पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है और फल और फूल आने के वक्त इसे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, जब कपास की फसल की कुल पानी की जरूरतों की 80 प्रतिशत जरूरत होती है।

- भारत में 67 प्रतिशत कपास का उत्पादन वर्षा पर निर्भर इलाकों में होता है
- कपास पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है और फल व फूल आने पर पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता
- बारिश पर निर्भर इलाकों में कपास का उत्पादन सिंचित क्षेत्रों की तुलना में कम होता है

उन्होंने कहा कि इसकी वजह से बारिश पर निर्भर इलाकों में कपास का उत्पादन सिंचित क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। खासकर महाराष्ट्र में ऐसा होता है, जहां 95 प्रतिशत क्षेत्र बारिश पर निर्भर है। साथ ही मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में भी बारिश के पानी की उपलब्धता कम रहती है।

गनात्रा ने कहा, 'इससे बाहर निकलने के लिए एसोसिएशन ने सरकार को बारिश पर निर्भर किसानों की मदद करने और उन्हें ड्रिप सिंचाई के इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है।'

उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा करती है तो हमारे कपास की उपज बढ़ेगी और ड्रिप सिंचाई से प्रभावी रूप से सिंचाई हो सकेगी और पानी की कुल जरूरत में से 40 से 60 प्रतिशत पानी की बचत होगी। गनात्रा ने कहा, 'भारत में ड्रिप सिंचाई से संबंधित संयंत्र लगाने की लागत बहुत ज्यादा है, ऐसे में हमने सरकार से अनुरोध किया है कि वह किसानों को बजट से कम से कम 500 करोड़ रुपये मुहैया कराए।'

एसोसिएशन ने कपास के आयात पर लगने वाले 5 प्रतिशत बेसिक सीमा शुल्क, 5 प्रतिशत कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर और 1 प्रतिशत सामाजिक कल्याण शुल्क हटाए जाने की भी मांग की है। यह कर वर्ष 2021-22 से लग रहा है, जिसे हटाने से भारत में आयात सस्ता होगा। भारत में इस साल कपास की मांग और आपूर्ति की स्थिति को लेकर गनात्रा ने कहा कि ताजा अनुमान के मुताबिक 2024-25 (अक्टूबर से सितंबर) में कपास का कुल रकबा 10 प्रतिशत घटकर 113.6 लाख हेक्टेयर रहने की संभावना है, जो पिछले साल 126.8 लाख हेक्टेयर था।

कृषि प्रसंस्करण यूनिट को बढ़ावा देने पर काम

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र के तहत कृषि प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने को प्रोत्साहित करने पर काम कर रही है। साथ ही सरकार गहरे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए मछुआरों को वित्तीय मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) का पंजीकरण पूरा होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगले 5 साल में 2,00,000 नए पीएसीएस स्थापित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बीमार पीएसीएल के परिसमापन के लिए नई मानक परिचालन व्यवस्था भी पेश की। उन्होंने कहा कि इससे स्वस्थ पीएसीएल की वृद्धि सुनिश्चित होगी।